ISSN: XXXX-XXXX
Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS)
© NIJMS | Vol. 1 | Issue 1 | August-September 2024
Available online at: https://nijms.com/

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन

अनिल कुमार खण्डेलवाल

शोधार्थी, R.R.B.M.U., अलवर (राजस्थान)

सहायक आचार्य, आर्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अलवर राज.

E-mail – anilkhandelwal333@gmail.com

सम्प्रत्यात्मक पृष्ठभूमि

शिक्षा मानव की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने, समाज व राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया है। यह शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओ को पूरा करना है। यह शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन भारतीय दर्शन, ज्ञान की समूह परम्परा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है। किसी भी देश के विद्यार्थियों का भविष्य उसके शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इस तथ्य को मनोवैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक समर्थन प्राप्त है। परंतु यह भी एक तथ्य है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षकों की योग्यता पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा की प्रणाली को बहुविषयक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से जोड़कर 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक डिग्री को स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्थापित करके यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों को अपने विषय, शिक्षण शास्त्र और शिक्षण अभ्यास में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। इसके लिए एक प्रभावकारी रणनीति के तहत शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है।

मूलशब्द : *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मानव, समाज व राष्ट्र, शिक्षक शिक्षा*

प्रस्तावना

शिक्षा मनुष्य को इस प्रकृति का सबसे अलग प्राणी बनती है, जैविक रूप से देखा जाए तो मनुष्य प्रकृति का सबसे कमजोर प्राणी है। अधिकांश जानवरों में मनुष्य से अधिक शक्ति है जैसे हाथी, शेर आदि जानवर मनुष्य से अधिक बलवान व श्रेष्ठ हैं कुत्ता, चीता जैसे जानवर मनुष्य से अधिक तेज भाग सकते हैं परंतु शिक्षा ही एक ऐसा तत्व है, जिससे मनुष्य प्रकृति के सभी जीवो पर अंकुश रख सकता है। शिक्षा से ही मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। इसी विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा की सार्वभौमिक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने तथा शिक्षा को समकालीन विश्व के साथ गति प्रदान करने के लिए शिक्षा नीतियां बनाई जाती हैं। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 भारत

द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य एसजी 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और सामान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के विस्तृत लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन देने और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी। ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

शिक्षा मानव की पूर्ण मानसिक क्षमता को प्राप्त करने का, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ व सरल होनी चाहिए, जिससे सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हो सके। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो देश की समृद्धि और आर्थिक विकास की कुंजी है। वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जिसमें सर्वाधिक संख्या युवा वर्ग की है। इसलिए भारत की कार्यक्षमता विश्व में सर्वाधिक है। इस कार्यक्षमता को उचित रूप से विकसित करने के लिए शिक्षा के अवसरों की समानता पर भी बल देना होगा। आज का युग तकनीकी का युग है, अतः शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ई–अधिगम, मशीनी लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं।आज के ज्ञान के परिदृश्य में संपूर्ण विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मशीनी अधिगम से ज्ञान के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं। शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह आवश्यक हो गया है, कि बालक सीखे गए ज्ञान को सतत सीखता भी रहे। 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य ''सभी को समानता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा''होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में छुपी हुई योग्यताओं एवं रचनात्मकता के विकास पर बल देती है। इस नीति का मूल सिद्धांत बुनियादी क्षमताओं के विकास के साथ तार्किक क्षमता, समस्या समाधान क्षमता का विकास, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के प्रकाश में तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय परंपरा में सदैव सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति माना जाता था। यह नीति भारतीय परंपराओं को दृढ़ करने एवं संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

शिक्षा व्यवस्था में किये जा रहे इन बुनियादी परिवर्तनों का केंद्र शिक्षक है। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को सेवा पूर्व पाठ्यक्रम में ही गुणवत्ता प्रदान करनी होगी। इसके लिए भी नई शिक्षा नीति 2020 में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। जिससे शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों में भी व्यावसायिक दृ ष्टिकोण उत्पन्न हो सके। वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए चल रहे है। इनमें प्राथमिक शिक्षक कार्यक्रम (D.El.Ed.), द्विवर्षीय स्नातक शिक्षा कार्यक्रम (B.Ed. 2 year) एवं एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (Integrated 4 year) प्रमुख हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा कर समाज को गति प्रदान करने में योगदान दे सके। इसके लिए स्कूल शिक्षा में भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। यहां नई शिक्षा नीति में स्कूली व्यवस्था को 5 + 3 + 3 + 4 की एक नई व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात कही गई है इसमें क्रमशः फाऊंडेशनल स्टेज दो भागों में अर्थात आंगनबाड़ी (प्री स्कूल के 3 साल तथा

प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 व 2 साल,3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित) प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3 से 5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित), मिडिल स्कूल स्टेज (कक्षा 6 से 8, 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित) और सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12 दो फेज में यानि पहले फेस में 9 और 10 और दूसरे में 11 व 12, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) शामिल होंगी। इस संपूर्ण व्यवस्था में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को मजबूत बनाने पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की भूमिका

नई शिक्षा नीति 2020 में जिस नए विद्यालय ढांचे की बात कही गई है, उसे धरातल पर लाने का कार्य शिक्षकों द्वारा ही किया जा सकता है, तथा शिक्षकों से पहले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इस व्यवस्था के लिए तैयार करना होगा। यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। शिक्षक शिक्षा को धीरे–धीरे वर्ष 2030 तक बहु–विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर प्राइमरी लेवल से हायर एजुकेशन तक काफी सारे बदलाव किए गए हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने अभी हाल ही में एक नया कोर्स शुरू किया है जिसका नाम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) है। इस कोर्स का उद्देश्य स्कूल संरचना के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को बुनियादी, प्रारंभिक मध्य और माध्यमिक चरणों के 5 + 3 + 3 + 4 के लिए तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम में केवल योग्य उम्मीदवार ही शिक्षण पेशे में प्रवेश कर सकता है। इस कोर्स में काफी सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी जैसे– भारतीय मूल्यों का ज्ञान, भाषाओं का ज्ञान, लोकाचार और आदिवासी परंपराओं का ज्ञान प्राप्त होगा। इससे छात्र को शिक्षा और शिक्षा शास्त्र में नवीनतम प्रगति के बारे में काफी जानकारी मिलती है।

NCTE पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023–24 से 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEI) में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ITEP शुरू किया है। मार्च 2023 में इस कोर्स को लांच किया गया। यह NEP 2020 के तहत NCTE का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ITEP को 26 अक्टूबर 2021 को अधिसूचित किया गया है। यह एक चार साल की दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है जो बी.ए. बी.एड., बी.एससी. बी.एड., और बी.कॉम. बी.एड., कोर्स ऑफर करती है। इस कोर्स से छात्रों को 1 वर्ष की बचत होगी। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (NCET) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम पूरे अध्यापक शिक्षा क्षेत्र के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे भारतीय मूल्यों और परंपराओं पर आधारित एक बहु–विषयक वातावरण के माध्यम से इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाले भावी शिक्षकों को 21वीं सदी के वैश्विक मानकों की आवश्कताओं से परिचित कराया जाएगा और इस प्रकार वे नए भारत के भविष्य को स्वरूप देने में अग्रणी भूमिका निभाएगें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा पर चर्चा तीन शीर्षकों ''शिक्षक, शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण तथा शिक्षक शिक्षा'' के अंतर्गत की गई है। इस नीति में शिक्षक शिक्षा में पहला बदलाव शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि व प्रकृति को लेकर है। वर्तमान में चल रहे 17 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जगह इस नीति में तीन कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। पहले 4 वर्षीय एकीकत बी.एड. कार्यक्रम जो डुएल मॉड का होगा अर्थात इसमें विद्यार्थी को प्रशिक्षित शिक्षक की उपाधि के साथ एक विशेष विषय में स्नातक डिग्री भी मिलेगी, दूसरा 2 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम इस पाठ्यक्रम में विषय विशेष में स्नातक डिग्री 3 वर्षीय हासिल कर चुके विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। इस कड़ी में तीसरा कार्यक्रम एक वर्षीय बी.एड. का होगा। जिसमें विषय विशेष में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रवेश ले सकेंगे। इन तीनों पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त यह नीति संस्थानों को अल्प अवधि

के शिक्षक कार्यक्रम चलाने का भी का विकल्प देती हैं। शिक्षक शिक्षा में दूसरा बदलाव शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं की प्रकृति से है। यह नीति यह बताती है कि शिक्षक शिक्षा को केवल बहु–विषयक संस्थानों में ही संचालित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक संस्थाओं के रूप में बदलने का लक्ष्य रखती है। बुनियादी शैक्षिक मांपदडों को पूरा न करने वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को गुणवत्ता के लिए यह नीति एक वर्ष का समय देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव शिक्षक शिक्षा की नियामक संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की भूमिका को लेकर है यह नीति एनसीटीई की रेगुलेटरी पावर को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (N.H.R.C.) को सौंपने की सिफारिश करती है। यह नीति NCTE से सामान्य शिक्षा परिषद (JEC) के सदस्य के रूप में पाठ्यक्रम संरचना शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने विभिन्न विषयों के शिक्षण अनुसंधान और विस्तार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा करती है।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति के सुझाए गए सभी सुझाव बहुत ही सराहनीय हैं परंतु पहले के अनुभव बताते हैं कि अच्छी नीतिया या तो क्रियान्वित नहीं हो पाती है या फिर लेट लतीफी का शिकार हो जाती हैं। हम शिक्षक शिक्षा के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते, यह आशा की जा सकती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाए गए बदलाव में अगला पड़ाव शिक्षक शिक्षा संबंधी नीति के क्रियान्वयन के तात्कालिक मध्य अवधि एवं दीर्घकालिक लक्ष्य तय कर उन्हें प्राप्त करने के तरीकों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा। इस क्रियान्वयन योजना के निर्माण से यह संदेश भी जाएगा कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीति व नीयत में कोई विरोधाभास नहीं है। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले वहां की शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को ही सुधारना होता है आशा है कि इस नीति में इस सिद्धांत को महत्व दिया जाएगा।

संदर्भ सूची

[1] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

[2] डॉ. सोमेश नारायण सिंह, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षक शिक्षा, IJCRT, VOL-8,ISSUE-9, SEP.-2020, ISSN: 2320-2882

[3] https://www.skoolbeep.com/blog/reforms-for-teachers-training-in-nep-2020/

[4] https://carrerupdates.in>itep

[5] www.junputh.com

[6] www.livehindustan.com

[7] https://leverageeda.com

Cite this Article:

अनिल कुमार खण्डेलवाल, " राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन", Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS), ISSN: XXXX-XXXX (Online), Volume 1, Issue 1, pp. 29-32, August-September 2024.

Journal URL: https://nijms.com/

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.